राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

रोकठोक लेखनी

RNI NO. : MAHHIN/2019/77511

खबरें बे-रोकटोक

वर्ष 07 ■ अंक 02 ■ मुंबई : बुधवार 12 नवंबर 2025 से 18 नवंबर 2025 ■ संपादक : फैसल शेख ■ पृष्ठ : 8 ■ कीमत : 03 रुपये

बीएमसी चुनाव 2025: लॉटरी से तय हुई एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण...

मुंबई : बीएमसी चुनाव 2025 : ब्रिहन्मुंबई महानगरपालिका ने आगामी निगम चुनाव 2025 के लिए वार्ड-वार आरक्षण सोडत (आरक्षण लॉटरी) की विस्तृत सूची जारी कर दी है। आधिकारिक मंच पर प्रदर्शित तालिका में अनु.जाति, अनु.जनजाति, नागरीक समन्वय (महिला), नागरीक समन्वय (सामान्य), सर्वसाधारण (महिला) और खुला वर्ग — सभी श्रेणियों के वार्ड नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। इस सूची के जारी होते ही मुंबई की राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है।

तालिका के अनुसार अनु.जाति SC (महिला) वर्ग में वार्ड 118, 133, 147, 151, 155, 183, 186 और 189 शामिल हैं। वहीं अनु.जनजाति वर्ग SC के लिए 26, 93, 140, 141, 146, 152 और 215 क्रमांक आरक्षित किए गए हैं। अनु.जाति महिला के लिए विशेष रूप से वार्ड 121 तथा अनु.जाति सामान्य श्रेणी के लिए वार्ड 53 को शामिल किया गया है।

सबसे अधिक सीटें नागरीक समन्वय (महिला) के अंतर्गत आती हैं, जिनमें वार्ड 1, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 27, 32, 33, 46, 49, 52, 72, 80 और 82 शामिल हैं। इसी श्रेणी में दूसरे कॉलम में 100, 105, 108, 117, 120, 128, 150, 153, 158, 167, 170, 176, 191, 198 और 216 दर्ज हैं। यह सूची दर्शाती है कि महिलाओं के लिए इस बार प्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है।

नागरीक समन्वय (सामान्य) वर्ग में वार्ड 4, 10, 15, 35, 50, 63, 69, 70, 76, 85, 87, 91, 95, 111 और 113 दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही इस श्रेणी में 130, 135, 136, 137, 171, 182, 187, 193, 195, 208, 219, 222, 223 और 226 जैसे वार्ड भी शामिल हैं, जो कुल मिलाकर बड़ी संख्या बनाते हैं।

महत्वपूर्ण श्रेणी सर्वसाधारण (महिला) में भी 74 की 74 सीटें सूचीबद्ध की गई हैं। इनमें वार्ड 2, 8, 14, 16, 17, 21, 24, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 44, 51, 56, 60 और 61 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 114, 115, 116, 120, 123, 131, 132, 139, 143, 142, 156, 157, 163, 172, 173, 174 और 175 जैसे वार्ड भी इस श्रेणी में आते हैं। तालिका में आगे 177, 179, 180, 190, 196, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 212, 224 और 227 भी दर्ज किए गए हैं।

सबसे बड़ी और खुली श्रेणी ''खुला वर्ग'' में इस बार 75 की 75 सीटें शामिल हैं। इन वार्डों में 3, 5, 7, 9, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 34, 36, 40, 43, 47, 48, 54, 55, 57, 59, 62, 65, 67, 68, 75, 86, 90, 92, 98, 99 और 102 शामिल हैं। इसके साथ ही 103, 104, 106, 109, 110, 118, 125, 126, 133, 144, 145, 148, 149, 154, 159, 160 और 161 भी इस श्रेणी में आते हैं। अंत में 162, 164, 165, 166, 169, 170, 178, 181, 185, 188, 190, 194, 200, 202, 204 और 206 के साथ 207, 210, 211, 214, 217, 221 और 225 का भी समावेश है।

बीएमसी द्वारा जारी यह व्यापक आरक्षण चार्ट शहर के सभी 227 वार्डों की नई संरचना और प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सूची जारी होने के साथ ही राजनीतिक दल अपने संभावित उम्मीदवारों पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर चुके हैं। महिलाओं की सीटों में बढ़ोतरी और खुला वर्ग में व्यापक प्रतिस्पर्धा इस चुनाव को पहले से अधिक रोचक और महत्वपूर्ण बना रही है।

महिम SRA परियोजना में बड़ा घोटाला उजागर:

39 PAP कमरों के गैर-हस्तांतरण पर SRA की सख्त कार्रवाई, ओम साईनाथ सोसायटी में अवैध बिक्री का आरोप

महिम : महिम क्षेत्र में चल रही SRA परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) ब्रिहन्मुंबई ने 12 सितंबर 2025 को डेवलपर M/s HRUB Relty Pvt. Ltd. को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि डेवलपर ने श्री गजानन सिद्धिविनायक SRA CHS के 39 PAP टेनेमेंट्स अभी तक SRA को नहीं सौंपे हैं। यह स्थिति परियोजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है, जिसके चलते SRA ने सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

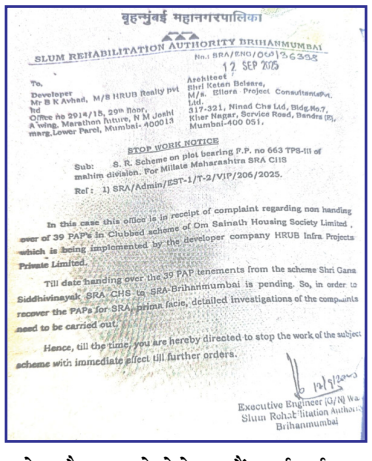

इसी बीच, ओम साईनाथ हाउसिंग सोसायटी में एक और गंभीर आरोप उभर कर सामने आया है। यहां PAPs के लिए निर्धारित पुनर्वसन फ्लैट कथित रूप से बाहरी लोगों को अवैध रूप से बेचे गए हैं। कई वर्तमान निवासियों के पास असली SRA अलॉटमेंट लेटर मौजूद नहीं है, जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि पुनर्वसन योजना के नाम पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है। यह न केवल महाराष्ट्र सरकार के साथ धोखाधड़ी है, बल्कि उन वास्तविक PAP लाभार्थियों के साथ भी अन्याय है, जिन्हें उनके वैध अधिकारों से वंचित किया गया। आरोप यह भी है कि पात्रता सूची और अलॉटमेंट प्रक्रिया में हेराफेरी कर बाहरी व्यक्तियों को फ्लैट उपलब्ध कराए गए।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

SLUM REHABILITATION AUTHORITY BRIHANMUMBAI

No.: SRA/ENG/06/136398

12 SEP 2025

To,
Developer
Mr B K Avhad, M/S HRUB Realty pvt ltd
Office no 2914/15, 29th floor, A wing, Marathon future, N M Joshi marg, Lower Parel, Mumbai- 400013

Architect
Shri Ketan Belsare,
M/s. Ellora Project Consultants Pvt. Ltd.
317-321, Ninad Chs Ltd, Bldg.No.7, Kher Nagar, Service Road, Bandra (E), Mumbai-400 051.

STOP WORK NOTICE

Sub: S. R. Scheme on plot bearing F.P. no 663 TPS-III of mahim division. For Millate Maharashtra SRA CHS

Ref: 1) SRA/Admin/EST-1/T-2/VIP/206/2025.

In this case this office is in receipt of complaint regarding non handing over of 39 PAP's in Clubbed scheme of Om Sainath Housing Society Limited, which is being implemented by the developer company HRUB Infra Projects Private Limited.

Till date handing over the 39 PAP tenements from the scheme Shri Gana Siddhivinayak SRA CHS to SRA-Brihanmumbai is pending. So, in order to recover the PAPs for SRA, prima facie, detailed investigations of the complaints need to be carried out.

Hence, till the time, you are hereby directed to stop the work of the subject scheme with immediate effect till further orders.

12/9/2025

Executive Engineer (G/N) Wa...
Slum Rehabilitation Authority
Brihanmumbai

इस पूरे मामले को देखते हुए शिकायतकर्ता ने SRA से ओम साईनाथ सोसायटी का विस्तृत सर्वे करने की मांग की है। इसमें सभी किरायेदारों की वास्तविक पहचान, अलॉटमेंट लेटर्स की जांच, मूल PAP दस्तावेजों का सत्यापन और MHADA/SRA के पात्रता रिकॉर्ड से क्रॉस-चेक शामिल है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि कई फ्लैट ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में हो सकते हैं, जो वास्तविक PAPs नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक फ्लैट का पुनः निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है।

12 सितंबर 2025 को जारी SRA के स्टॉप-वर्क नोटिस ने मामले की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। नोटिस में यह कहा गया है कि डेवलपर HRUB Relty ने न केवल 39 PAP टेनेमेंट्स का हस्तांतरण रोका है, बल्कि परियोजना में SRA के दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया। इस वजह से कई सोसायटियों में पुनर्वसन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और यह संदेह भी जताया गया है कि निर्माण कार्य और फ्लैट अलॉटमेंट में धोखाधड़ी जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं।

SRA ने इसलिए सभी कार्यों पर रोक लगाते हुए जांच पूरी होने तक डेवलपर को आगे कोई गतिविधि न करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने SRA से आग्रह किया है कि वह तुरंत साइट निरीक्षण करे, अवैध रूप से बेचे गए फ्लैटों की पहचान करे और असली PAPs को उनका वैध अधिकार वापस दिलाए। साथ ही, डेवलपर्स और एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है, ताकि पुनर्वसन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और गरीब PAP परिवारों के साथ दोबारा अन्याय न हो। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि यह मामला सरकार को बड़े वित्तीय नुकसान पहुँचाता है और इसलिए इसकी रिपोर्ट मुंबई पुलिस को देकर आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पूरी स्थिति को देखते हुए SRA की भूमिका अब अत्यंत अहम हो गई है, क्योंकि यह मामला केवल एक सोसायटी या एक डेवलपर का नहीं, बल्कि पूरे पुनर्वसन तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। PAPs को न्याय दिलाने और सरकारी योजनाओं का सही लाभ सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

अमेरिकी शुल्क पर विवाद...

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में सुनवाई तेज कर दी है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर एकतरफा शुल्क लगाने के अधिकार को चुनौती दी गई है। आमतौर पर न्यायालय लंबे समय तक सुनवाई करता है और गर्मियों में अपना निर्णय देता है। परंतु ऐसा लगता है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी निपट जाएगी। पिछले सप्ताह न्यायालय में बहस का जो दौर चला उसमें उन वकीलों की स्थिति मजबूत नहीं दिख रही थी जो कार्यपालिका को शुल्क तय करने का अधिकार देने वाले 1977 की एक व्यवस्था का बचाव कर रहे थे। यह कहता है कि आपातकालीन व्यापार उपायों को विधायिका के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक रूप से, शुल्क और सभी प्रकार के कर लगाने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के पास सुरक्षित है, लेकिन ट्रंप ने इस दशकों पुराने आपातकालीन अधिकार का उपयोग करके अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही व्यापार नीति को प्रभावी रूप से पलट दिया है। विभिन्न वजहों से सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के 9 न्यायाधीशों में से अधिकांश इस कदम को लेकर आशंकित हैं। इनमें से कई तो स्वयं ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति, खुद भी थोड़े असहज नजर आ रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर अपनी शुल्क नीति की आलोचना करने वालों को 'मूर्ख' घोषित किया जो यह नहीं मानते हैं कि अमेरिका अब दुनिया का 'सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश है जहां न के बराबर मुद्रास्फीति है और जिसके शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं।'

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

घोड़बंदर रोड पर चल रहे सभी कार्य 31 दिसंबर तक पूरे हो जाएँगे

रोजमर्रा के ट्रैफि क जाम से मिल सकती है राहत...

मुंबई : घोड़बंदर रोड (जीबी रोड) का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को जल्द ही रोजमर्रा के ट्रैफि क जाम से राहत मिल सकती है। ठाणे नगर निगम (टीएमसी) ने घोषणा की है कि इस प्रमुख मार्ग पर चल रहे सभी कार्य 31 दिसंबर तक पूरे हो जाएँगे।टीएमसी आयुक्त ने वादा किया है कि दिसंबर 2025 तक घोड़बंदर रोड पर यातायात सुचारू हो जाएगा क्योंकि इस मार्ग का 90 प्रतिशत काम टीएमसी और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।सोमवार को टीएमसी मुख्यालय में एक बैठक में, टीएमसी आयुक्त सौरभ राव ने परिवहन मंत्री और विधायक प्रताप सरनाईक और एमएमआरडीए, म्हाडा, पीडब्ल्यूडी और ठाणे ट्रैफि क पुलिस के

अधिकारियों की उपस्थिति में यह घोषणा की। राव ने कहा, ''मार्ग का 90 प्रतिशत काम दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा, और बाकी काम फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। नए साल से, वाहन चालक जीबी रोड पर सुचारू यातायात की उम्मीद कर सकते हैं।''वर्तमान में, मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क की मरम्मत, पानी की पाइपलाइन बिछाने, सर्विस रोड को जोड़ने, यूटिलिटी लाइनों को दूसरी जगह लगाने और कंक्रीट बिछाने जैसे कई कार्य चल रहे हैं, जिससे व्यस्त समय में लेन बंद हो रही हैं और यातायात जाम की स्थिति बनी हुई है।बैठक में शामिल सामाजिक कार्यकताओं ने कार्यस्थलों पर समन्वय और सुरक्षा उपायों की कमी पर कड़ी आपत्ति जताई। कार्यकर्ता श्रद्धा राय ने नगर निगम और परिवहन अधिकारियों के ''लापरवाह रवैये'' की आलोचना की और आरोप लगाया कि ''सुरक्षा प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने टीएमसी से आग्रह किया कि बार-बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए सभी फ्लाईओवरों की मरम्मत की जाए और गायमुख घाट खंड की मरम्मत भी एक साथ की जाए।घोड़बंदर रोड लंबे समय से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम, खराब सड़क की वजह से दुर्घटनाएँ होती हैं और सुरक्षा संकेतों की कमी होती है। मेट्रो रेल के चल रहे निर्माण कार्य ने बैरिकेड्स और लेन बंद होने से स्थिति और खराब कर दी है। हाल के महीनों में औजारों और सीमेंट की बोरियों के गिरने की कई घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे जन सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।यह सड़क जेएनपीटी और गुजरात व राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों के बीच माल परिवहन करने वाले ट्रकों के लिए एक महत्वपूर्ण माल ढुलाई गलियारा भी है।

महाविकास अघाड़ी ने स्पष्ट किया; लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मनसे के साथ चुनाव लड़ेंगे

मुंबई : मतदाता सूची में गड़बड़ी, डुप्लीकेट मतदाता, गलत पते को देखते हुए, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव सूचियों में सुधार के बाद ही कराए जाने चाहिए, जबकि विपक्ष मांग कर रहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों (कुल 288) के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सदस्य और प्रत्यक्ष महापौर पद के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा; जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मनसे महाविकास अघाड़ी में शामिल होने को लेकर असहमति है। नासिक में मनसे और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य का फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे। हालांकि, नासिक में महाविकास अघाड़ी ने स्पष्ट किया कि हम मनसे के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया गया है। आगामी सभी चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया गया है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार जातियों के बीच टकराव पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। माकपा नेता डी. एल. कराड ने कहा कि हमने महाराष्ट्र में आगामी चुनावों में महायुति के प्रभाव को कम करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया है।

लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में वोट चोरी के दम पर सरकार सत्ता में आई है। मुंबई में एक संयुक्त मार्च निकाला गया। 96 लाख दोहरे मतदाता हैं। शिंदे की सेना ने कहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम सूखे और कर्ज माफी के लिए लड़ रहे हैं, मनसे नेता दिनकर पाटिल ने कहा। इस बीच, हम जनता के पक्ष में खड़े रहेंगे। केवल देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही सारी शक्ति है।

पीएमसी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक मुख्य आरोपी जॉय थॉमस के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज

मुंबई : भांडुप पुलिस ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और बैंक तथा रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) से जुड़े ₹4,635 करोड़ के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी जॉय थॉमस के खिलाफ धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है।जॉय थॉमस, जिन्हें 27 सितंबर, 2019 को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी बैंक के एमडी पद से निलंबित कर दिया गया था।जॉय के साथ, पुलिस ने बैंक की पूर्व मुख्य प्रबंधक और एमडी की सचिव कमलजीत कौर और रियल एस्टेट फर्म शुभम कमर्शियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों निमित छेड़ा और रुचिक छेड़ा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।यह मामला पीएमसी बैंक द्वारा 2018 में शुभम कमर्शियल एंटरप्राइजेज से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अनिवार्य जानकारी दिए बिना ₹14.5 करोड़ मूल्य की संपत्ति खरीदने से जुड़ा है।

पुलिस के अनुसार, बैंक ने नई शाखा स्थापित करने के लिए रियल एस्टेट फर्म द्वारा विकसित पनवेल परियोजना में तीन दुकानें और 30 कार्यालय खरीदे थे। हालाँकि, फर्म ने कथित तौर पर न तो संपत्तियों का कब्जा सौंपा और न ही पैसे वापस किए।पुलिस ने कहा कि पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने लापरवाही बरती और संपत्ति खरीदते समय नियमों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हुआ और बिल्डर को लाभ हुआ। बैंक के उपनियमों के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार और आरबीआई, दोनों को संपत्ति लेनदेन के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था।यह मामला यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने 2019 में धोखाधड़ी के सामने आने के बाद आरबीआई द्वारा अनिवार्य विलय के बाद 2022 में पीएमसी बैंक का अधिग्रहण किया था।

नवजात शिशुओं को शहर के अलग-अलग हिस्सों में लावारिस पाए जाने के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी

मुंबई : पिछले कुछ महीनों में, मुंबई में नवजात शिशुओं को शहर के अलग-अलग हिस्सों में लावारिस पाए जाने के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है - रेलवे स्टेशन के इलाकों से लेकर सुनसान गलियों और पब्लिक टॉयलेट तक। ये घटनाएं कमजोर शिशुओं की सुरक्षा और कुछ माता-पिता को ऐसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर करने वाली मजबूरी के बारे में गंभीर सामाजिक और नैतिक सवाल खड़े करती हैं। सितंबर के आखिर और अक्टूबर के बीच, शहर में ऐसी चार घटनाएं रिपोर्ट की गईं।

27 अक्टूबर को, बोरीवली ईस्ट के अशोकवन में एक नाले में एक नवजात बच्ची मिली, जिसे तुरंत बचाया गया और कांदिवली वेस्ट के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि बच्ची के माता-पिता - मां, जो एक घरेलू काम करने वाली है, और पिता, जो दिहाड़ी मजदूर है - ने आर्थिक तंगी के कारण बच्ची को छोड़ दिया था। इस जोड़े की पहले से ही तीन बेटियां थीं और उन्होंने चौथी बेटी को जन्म दिया था। 20 अक्टूबर को, मालाड वेस्ट में एंथनी टॉवर के पीछे चींटियों के काटने से घायल एक नवजात बच्ची मिली। उसे तुरंत शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, और पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

मुंबई : घरेलू काम करने वाली महिला का सेक्शुअल असॉल्ट; ड्रग्स देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई : माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक चौंकाने वाले मामले में, पुलिस ने 37 साल के एक ड्राइवर, इंद्र मोहन गजेंद्र भारती उर्फ कामत को एक 35 साल की घरेलू काम करने वाली महिला का सेक्शुअल असॉल्ट करने, उसे ड्रग्स देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी, जो मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है, को वालकेश्वर में खंडोबा मंदिर के पास से पकड़ा गया। आरोपी ने एक ही जगह का होने का फायदा उठाकर पीड़िता से दोस्ती की शिकायत के मुताबिक, 35 साल की पीड़िता, जो दक्षिण मुंबई में घरेलू काम करती है, 2024 में ओपेरा हाउस में एक घर में काम करते समय आरोपी के संपर्क में आई थी। इंद्र मोहन, जो वहां ड्राइवर के तौर पर काम करता था, उसने पीड़िता से दोस्ती कर ली क्योंकि दोनों बिहार के एक ही जिले के रहने वाले थे।

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का सेंट्रल ऑफिस क सीनियर क्लर्क 21.80 लाख के गबन के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई : नागपाड़ा पुलिस ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सेंट्रल ऑफिस के एक सीनियर क्लर्क को इनकम टैक्स पेमेंट के लिए रखे गए ₹21.80 लाख के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी हो गई है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ऑडिट से गबन का पता चला महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सेंट्रल ऑफिस, नायर रोड, मुंबई में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर अमोल शेलार (45) की शिकायत के अनुसार, आरोपी प्रथमेश कैलाश पवार कॉन्ट्रैक्टर के बिल बनाने और टैक्स पेमेंट मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदार था। अलग-अलग महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ब्रांच से इकट्ठा किए गए फंड को ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने से पहले कॉर्पोरेशन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में जमा करना था।

कपल और उनके साथी के खिलाफ फ्लैट दिलाने के बहाने 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज

मुंबई : साकीनाका पुलिस ने पवई के एक कपल और उनके साथी के खिलाफ एक 62 साल के बिजनेसमैन से महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) का फ्लैट दिलाने के बहाने 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता और पीड़ित रमेश नागफासे हैं, और आरोपी करुणाकर पुजारी, उनकी पत्नी सुनीता पुजारी और उनके साथी सनी कांबले हैं। 7 नवंबर को दर्ज ऋक्ष के मुताबिक, नागफासे साकीनाका में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान चलाते हैं। आरोपी पुजारी कपल पवई की लेक व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता है। पहले नागफासे और पुजारी साकीनाका में एक ही इलाके में रहते थे और एक-दूसरे को जानते थे। कपल ने नागफासे से दोस्ती कर ली और धीरे-धीरे उनका भरोसा जीत लिया।

मुंबई : होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार होने के बावजूद, अंतिम रूप नहीं...

मुंबई : घाटकोपर में तेज हवाओं के बीच 120ग120 फीट का एक बड़ा बिलबोर्ड गिर गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के एक साल से भी ज्यादा समय बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अपनी संशोधित होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार करने और व्यवस्थागत बदलावों की सिफारिश करने वाली एक विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के बावजूद, अभी तक उसे अंतिम रूप नहीं दिया है। घाटकोपर में तेज हवा और धूल भरी आंधी के बाद पेट्रोल पंप पर बिलबोर्ड गिरने के बाद, मुंबई फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और बीएमसी द्वारा घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है।13 मई, 2024 की दुर्घटना के बाद नगर निकाय द्वारा नए होर्डिंग की अनुमति रोक दिए जाने के बाद से, मुंबई को लाइसेंस शुल्क के रूप में संभावित रूप से ₹16-17 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रत्येक नए होर्डिंग से

निगम को आम तौर पर लगभग ₹24 लाख सालाना की कमाई होती है, और हर साल लगभग 50 प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

हालाँकि, संशोधित अनुमतियाँ तब तक स्थगित रखी गई हैं जब तक मसौदा नीति को मंजूरी नहीं मिल जाती। अगस्त 2024 में, बीएमसी ने आउटडोर विज्ञापन नीति, 2024 का मसौदा प्रकाशित किया, जिसमें कड़े मानदंडों का प्रस्ताव रखा गया। इनमें होर्डिंग का आकार 40 फीट ७ 40 फीट तक सीमित करना, नवीनीकरण अवधि को छह महीने से घटाकर तीन महीने करना, ट्रैफि क आइलैंड, मीडियन, फुटपाथ और हाई-टेंशन बिजली लाइनों पर होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाना और संरचनात्मक स्थिरता जाँच अनिवार्य करना शामिल है। इसमें होर्डिंग के बीच न्यूनतम दूरी 100 मीटर से घटाकर 70 मीटर करने का भी प्रस्ताव रखा गया।अगले कुछ महीनों में नागरिकों, विज्ञापनदाताओं और उद्योग समूहों से सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं, जिनमें से कई ने तर्क दिया कि ये नियम या तो अत्यधिक प्रतिबंधात्मक थे या शहर में दृश्य अव्यवस्था बढ़ाने का जोखिम पैदा करते थे।इसके अलावा, राज्य सरकार ने घाटकोपर हादसे की जाँच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिलीप भोसले समिति का गठन किया।

समिति ने मई 2025 में सरकार को 650 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आईएस चहल के नेतृत्व में एक समीक्षा समिति ने इसकी 150 से ज्यादा सिफारिशों की जाँच की और राज्य मंत्रिमंडल को एक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी, जिसने हाल ही में सभी एजेंसियों को एक महीने के भीतर 21 सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।इन समानांतर प्रक्रियाओं के पूरा होने के बावजूद, मसौदा नीति नगर प्रशासन से आगे नहीं बढ़ पाई है। अब अंतिम निर्णय अतिरिक्त नगर आयुक्त विपिन शर्मा और नगर आयुक्त भूषण गगरानी को लेना है। एक नगर निगम अधिकारी ने कहा, ''लाइसेंस विभाग ने मसौदा नीति प्रस्तुत कर दी है और जनता द्वारा सुझाए गए बदलावों को संकलित कर लिया है।''

मुंबई : राकांपा नेता जीशान सिद्दीकी को धमकाने और क्रिकेटर रिंकू सिंह से जबरन वसूली करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत...

मुंबई : सत्र अदालत ने 33 वर्षीय एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता जीशान सिद्दीकी को धमकाने और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने का दावा करके भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से जबरन वसूली करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अप्रैल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता जीशान सिद्दीकी को कई ईमेल भेजे थे, जिनमें ₹10 करोड़ की मांग की गई थी और खुद को दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से जुड़ा होने का दावा किया गया था।

मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद नौशाद के रूप में पहचाने गए आरोपी की पहचान बिहार के निवासी मोहम्मद दिलशाद के रूप में हुई है, जो कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था। नौशाद को 1 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर उतरने के तुरंत बाद शहर की अपराध शाखा के जबरन वसूली विरोधी प्रकोष्ठ (एईसी) ने हिरासत में लिया था। मई की शुरूआत में, जाँचकताओं द्वारा उसके आईपी एड्रेस पर धमकी भरे कई ईमेल मिलने के बाद, उसके खिलाफ एक 'लुकआउट' सर्कुलर जारी किया गया था।पुलिस के अनुसार, नौशाद ने अप्रैल में सिद्दीकी को कई ईमेल भेजे थे, जिनमें ₹10 करोड़ की माँग की गई थी और खुद को दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से जुड़ा बताया गया था।

इन संदेशों में, उसने अक्टूबर 2024 में जीशान के पिता, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या का ज़िक्र करते हुए कहा था कि इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह नहीं, बल्कि डी-कंपनी का हाथ है।जाँच से पता चला कि नौशाद ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी उनके ब्रांड अभियान से जुड़े एक ईमेल अकाउंट के जरिए जबरन वसूली के संदेश भेजे थे। 5 फरवरी को अपने पहले संदेश में, नौशाद ने आर्थिक मदद की माँग की, लेकिन बाद में 9 अप्रैल को, उसने फिर से दाऊद के गिरोह का नाम लेते हुए ₹5 करोड़ की माँग की। पुलिस ने बताया कि 20 अप्रैल को, उसने धमकी दोहराते हुए एक रिमाइंडर ईमेल भेजा।जहाँ नौशाद के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठे अपराधों में फँसाया गया है, वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता पर जोर दिया और जमानत पर रिहा होने पर नौशाद के फरार होने की संभावना पर जोर दिया।हालाँकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.पी. देसाई ने पाया कि पुलिस रिपोर्ट में नौशाद के किसी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड का ज़िक्र नहीं है। अदालत ने कहा, ''जमानत के स्वरूप में विवेकाधिकार का प्रयोग आवेदक के पक्ष में कुछ शर्तों के साथ किया जा सकता है,'' और उसे ₹50,000 के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया।

मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट के इंजन में अचानक खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग

मुंबई : मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG670 के एक इंजन में अचानक खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट को सुरक्षित रूप से उतारा गया और 23.38 बजे पूरी तरह से आपातकालीन स्थिति हटा ली गई। कोलकाता हवाई अड्डा अधिकारी ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हुए हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग; रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश, सामूहिक अवकाश पर चले गए

मुंबई : जुहू स्थित डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल की कार्यवाहक डीन डॉ. नीलम एंड्रेड ने जुहू पुलिस को पत्र लिखकर 8 नवंबर की रात 12:10 से 12:30 बजे के बीच ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हुए हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।बीएमसी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केईएम अस्पताल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात की।उसी दिन सुबह एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, 30 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया और वे विरोध में सामूहिक अवकाश पर चले गए। पुलिस के अनुसार, आरोपी 35 वर्षीय समीर अब्दुल जब्बार शेख ने शनिवार को अपनी 57 वर्षीय माँ सैयदा को मृत घोषित किए जाने के बाद तीन डॉक्टरों पर हमला किया।

चूँकि उनका रक्तचाप रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, इसलिए डॉक्टरों ने वरिष्ठों को सूचित करने के बाद सीपीआर शुरू किया, लेकिन उन्हें होश में नहीं लाया जा सका।शेख ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ईएमएस) वार्ड के अंदर डॉक्टरों पर हमला किया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए: कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) डॉ. गौरव आनंदगांवकर, इंटर्न डॉ. प्रशांत भड़के और रेजिडेंट डॉ. करण देसाई।रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि घटना के दौरान किसी भी सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप नहीं किया। डॉ. देसाई ने कहा, ''मुझ पर मेरे अस्पताल के अंदर हमला किया गया, वही जगह जहाँ मैंने पिछले सात साल लोगों की

जान बचाने में बिताए हैं। किसी को भी सिर्फ. अपना काम करने के लिए हिंसा का सामना नहीं करना चाहिए, खासकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं।

बीएमसी महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एमएआरडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केईएम अस्पताल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात की और कूपर अस्पताल में हमला किए गए डॉक्टरों के लिए शीघ्र न्याय की गुहार लगाई।बीएमसी के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, ''हम नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। निवासियों ने पिछले तीन दिनों से सामूहिक अवकाश लिया हुआ था, जिससे हमारी सेवाओं पर कुछ हद तक असर पड़ा। हालाँकि, हम उनकी चिंताओं को समझते हैं। एफआईआर ड्यूटी पर तैनात सीएमओ ने दर्ज की थी, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। हमने जुहू पुलिस को एक और पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। चूँकि अपराध में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए एक नोटिस जारी किया गया है और पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामला जल्द ही उच्च न्यायालय में उठाया जाएगा।''एचटी द्वारा संपर्क किए जाने पर, जुहू पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील जाधव ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर के अनुसार, आरोपियों को जाँच के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है।

जाधव ने कहा, ''हमने एफआईआर की धाराओं के अनुसार जो आवश्यक था, वह किया है।''स्वास्थ्य अधिकारी ने आगे बताया कि अस्पताल में वॉकी-टॉकी से लैस आठ कर्मियों को तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सुरक्षा बल तैनात करने का एक प्रस्ताव भी रखा गया है और इसे लागू होने में लगभग तीन महीने लगेंगे। इस बीच, हम डॉक्टरों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं,'' अधिकारी ने कहा।कूपर एमएआरडी के प्रतिनिधि डॉ. चिन्मय केलकर ने एचटी को बताया, ''जब तक हमारी माँगें कागजी तौर पर पूरी नहीं हो जातीं, हम सामूहिक अवकाश पर हैं। हम आज उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में हुई सभी चचाओं की लिखित पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हम अगले कदमों पर फैसला लेंगे।''अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल इंटर्न की अनुपस्थिति के कारण सोमवार को कूपर अस्पताल में मरीजों का रक्तचाप मापने जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रभावित रहीं।

सड़क सुरक्षा, यातायात अनुशासन और जन जागरूकता के लिए वार्षिक बजट का 1% आवंटित करने का आदेश...

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में, सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राज्य सरकार को दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहनों में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने के आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। यह निर्देश पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और दुर्घटना के आंकड़ों के मद्देनजर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 70% सड़क दुर्घटनाएँ दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के कारण होती हैं।' महाराष्ट्र सरकार ने एक परिपत्र जारी कर राज्य के सभी नगर निगमों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार सड़क सुरक्षा, यातायात अनुशासन और जन जागरूकता पहलों के लिए अपने वार्षिक बजट का 1% आवंटित करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही, ₹74,427 करोड़ के वार्षिक बजट वाली बीएमसी को सड़क सुरक्षा पहलों पर ₹744 करोड़ खर्च करने होंगे।सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली समिति महाराष्ट्र के पाँच दिवसीय दौरे पर है और सोमवार को मुख्य सचिव राजेश कुमार से मुलाकात की। समिति सड़क सुरक्षा पर अदालत के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। बैठक में यातायात पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण, स्कूली शिक्षा और ग्रामीण विकास विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।समिति ने पिछले महीने दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ''70% सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन और पैदल यात्री शामिल होते हैं, इस आंकड़े पर प्रकाश डालते हुए, समिति ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अगले छह महीनों में दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले सवारों के लिए अनिवार्य हेलमेट का आदेश लागू हो।

उन्होंने आगे कहा, ''सभी चार पहिया वाहन चालकों के लिए भी इसी तरह के नियम लागू किए जाने की उम्मीद है। समिति ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि चूँकि इस मुद्दे की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है, इसलिए कार्यान्वयन में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।''अधिकारी ने कहा कि मुंबई और एमएमआर के कुछ हिस्सों को छोड़कर, हेलमेट अनिवार्यता का सख्ती से पालन नहीं किया गया और इन जगहों पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट का नियम भी लागू नहीं किया गया।समिति ने सड़कों की खराब संरचना, डिजाइन और रखरखाव में खामियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार सड़क ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर भी जोर दिया। राज्य सरकार को दुर्घटनाओं में 35% की कमी लाने का लक्ष्य रखने का भी निर्देश दिया गया है। 2024 में राज्य में 14,565 घातक दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 22,051 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 15,715 लोगों की मौत हुई। 2025 में, 30 सितंबर तक 10,720 घातक दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 11,532 मौतें हुईं।राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को कुछ उपाय करने का निर्देश दिया है, जिसमें फुटपाथ, जेबरा क्रॉसिंग और फुटओवर ब्रिज का ऑडिट शामिल है, जिसमें स्कूलों, धार्मिक स्थलों और रेलवे स्टेशनों के पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को अतिक्रमण, सड़कों और फुटपाथों की खराब गुणवत्ता आदि से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कैमरे, जीआईएस मैपिंग और एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर के अपने आदेश में सभी राज्य सरकारों को दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था।

3 लाख 50 हजार रुपये का इनाम घोषित माओवादी ने किया आत्मसमर्पण

गोंदिया : महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही नक्सल आत्मसमर्पण योजना का लाभ उठाते हुए दलम सदस्य जहाल माओवादी वर्गेश उर्फ कोसा मंगलू उइका (26, निवासी बेदरे, डाकघर जगरगुंडा) ने गोंदिया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वर्गेश पर 3 लाख 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वह बचपन से ही नक्सल आंदोलन में शामिल था। माओवादी संगठन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और अत्याचारों से तंग आकर वर्गेश ने सोमवार को जिला कलेक्टर प्रजीत नायर और पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित माओवादी वर्गेश उर्फ कोसा का पैतृक गांव सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, इसलिए उसके गांव में शुरू से ही हथियारबंद वर्दीधारी माओवादियों का आना-जाना लगा रहता था। माओवादियों के बहकावे और प्रलोभनों का शिकार होकर वह बचपन से ही नक्सल आंदोलन में भाग लेता रहा था और उनके निर्देशानुसार बाल संगठन में काम करता रहा था। हालाँकि, उन्होंने बताया कि नक्सल आंदोलन के नाम पर वरिष्ठ कमांडर की मनमानी, धन के नाम पर लूट, झूठे लक्ष्य और नीतियाँ, छल, प्रलोभन, हिंसा, इन सबका असली चेहरा सामने आने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया।

2016 में दलम की सदस्यता वर्गेश बचपन से ही नक्सल आंदोलन से जुड़े रहे और एक बाल संगठन में काम करते रहे। हालाँकि, सितंबर 2016 में उन्हें जगरगुंडा दलम में भर्ती किया गया। उन्हें जगरगुंडा क्षेत्र में एक महीने का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। फिर अक्टूबर 2016 में उन्हें दक्षिण गढ़चिरौली डिवीजन के भामरागढ़ एरिया कमेटी की पीएल-7 में भेजा गया। उन्होंने वहाँ लगभग दो महीने तक काम किया। इसके बाद, उन्होंने जनवरी 2017 से फरवरी 2020 तक गट्टा दलम के साथ काम किया। इसके बाद, उन्हें फरवरी 2020 में भामरागढ़ क्षेत्र में भेजा गया। उन्होंने अप्रैल 2021 तक भामरागढ़ दलम और सीएनएम (चेतना नाट्य मंच) में दलम सदस्य के रूप में काम किया है।

विभिन्न अपराधों में सक्रिय भागीदारी

2016 से 2021 तक नक्सली संगठन में काम करते हुए, उन्होंने बताया है कि वे सुरजागढ़ जलपोल (गढ़चिरौली जिला), मोहंदी गोलीबारी, बेसेवाड़ा गोलीबारी, दरधा जंगल गोलीबारी, येड्डामी जंगल घात, बोरिया कसनसुर गोलीबारी, गुंडरवाही गोलीबारी, गुरजा (ब) में एक पुलिस मुखबिर की हत्या, जरेवाड़ा गोलीबारी, कोपरशी-पोयरकोठी गोलीबारी, दुदेपल्ली-येड्डामर्मी गोलीबारी, कोठी गोलीबारी, कोठी में एक पुलिस मुखबिर की हत्या, कोपशी गोलीबारी आदि जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं।

महाराष्ट्र की 53% से ज्यादा ज़िला परिषदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया...

मुंबई : जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र की 53% से ज्यादा ज़िला परिषदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने बताया कि 22% से ज्यादा पंचायत समितियों, यानी तालुका-स्तरीय ग्रामीण निकायों में भी आधे से ज्यादा सीटें अनुसूचित जाति (रउ), अनुसूचित जनजाति (रळ) और अन्य पिछड़ा वर्ग (डइउ) के लिए आरक्षित हैं। विक्रमगढ़ तालुका में लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र की ओर जाते मतदाता।सीमा के उल्लंघन को अदालत में चुनौती दिए जाने की उम्मीद है। बॉम्बे उच्च न्यायालय पहले से ही चक्रीय आरक्षण, वार्ड गठन और अन्य चुनाव-पूर्व मामलों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में लगभग 50% मतदाता ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भाग लेते हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र राज्य भर में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कर रहा है, जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर निगम के चुनाव शामिल

हैं।जिला कलेक्टर, जो आरक्षण सहित चुनाव-पूर्व तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए ज़िम्मेदार हैं, ने इस सप्ताह की शुरूआत में 32 ज़िला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए कोटा की घोषणा की। हालाँकि ओबीसी कोटा 27% से अधिक नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय जनसंख्या के अनुसार एससी और एसटी का अनुपात अलग-अलग रहा है। एससी या एसटी की बहुलता वाले कई ज़िलों और तालुकाओं में, कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया है।ज़िला परिषदों की 2,882 सीटों में से 1,875 एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए केवल 1,007 सीटें ही बची हैं। 3,858 पंचायत समिति सीटों में से 1,906 सीटें आरक्षित हैं। हालाँकि सामान्य सीटों की कुल संख्या ज्यादा है, फिर भी कुछ निकायों ने इस अंतर को पार कर लिया है।नंदुरबार, पालघर और नासिक जैसे ज़िलों में, जहाँ आदिवासी आबादी ज्यादा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए काफी सीटें आरक्षित हैं। नंदुरबार ज़िला परिषद में 56 में से 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि पालघर में 57 में से 37 सीटें आरक्षित हैं।

इसी तरह, वाशिम, बुलढाणा और हिंगोली जैसे अनुसूचित जाति-बहुल ज़िलों में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए काफी सीटें आरक्षित हैं।राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के महासचिव सचिन राजुरकर ने कहा कि इस सीमा के उल्लंघन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ''सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2021 को ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था क्योंकि यह 50% की सीमा को पार कर गया था और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को बिना ओबीसी आरक्षण के पाँच ज़िला परिषदों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

मुंबई : आपातकालीन अपेंडिक्स सर्जरी की जरूरत...

एचआईवी पॉजिटिव मरीज को सर्जरी करने से मना कर दिया गया; एमडीएसीएस ने दिए जाँच के आदेश

मुंबई : आपातकालीन अपेंडिक्स सर्जरी की जरूरत वाले एक 37 वर्षीय एचआईवी पॉजिटिव मरीज को कथित तौर पर समय पर सर्जरी करने से मना कर दिया गया और उसे कहीं और इलाज कराने से पहले तीन सरकारी अस्पतालों के बीच चक्कर लगवाना पड़ा। इस घटना के बाद मुंबई ज़िला एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एमडीएसीएस) ने संभावित चिकित्सा लापरवाही और भेदभाव की जाँच शुरू कर दी है।एचआईवी पॉजिटिव मरीज को सरकारी अस्पतालों के बीच चक्कर लगवाना पड़ा; एमडीएसीएस ने जाँच के आदेश दिए बोरीवली निवासी मरीज को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद 31 अक्टूबर को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अल्ट्रासाउंड सहित अन्य जाँचों

में सब-एक्यूट अपेंडिक्साइटिस का पता चला, एक ऐसी स्थिति जिसमें आमतौर पर संक्रमण या फटने जैसी जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता होती है। फिर भी, आपातकालीन श्रेणी में आने के बावजूद, सर्जरी नहीं की गई। इसके बजाय, उस व्यक्ति को उसी दिन छुट्टी दे दी गई और कूपर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जब वह कूपर पहुँचा, तो डॉक्टरों ने रेफरल के आधार पर सवाल उठाया और उसे वापस भेज दिया, जिसके बाद मरीज को नायर अस्पताल भेज दिया गया। अंततः उसका वहीं इलाज हुआ।

पहले से ही एक पुरानी और कलंकित स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे मरीज के लिए यह अनुभव बेहद कष्टदायक था। उन्होंने कहा, ''मैं दर्द में था और मुझे मदद की जरूरत थी। लेकिन सर्जरी के बजाय, मुझे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने को कहा गया।'' उन्होंने आगे कहा, ''शताब्दी मेरे घर के पास एकमात्र सरकारी अस्पताल है। दर्द और डर के मारे लंबी दूरी तय करने से स्थिति और भी बदतर हो गई। मैं सोचता रहा कि क्या यह मेरी एचआईवी स्थिति के कारण हो रहा है।

अब वह घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।इस घटना ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कलंक को लेकर असहज सवाल खड़े कर दिए हैं, एक ऐसी चिंता जो सामुदायिक स्वास्थ्य समूहों का कहना है कि वर्षों से चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद बनी हुई है। एमडीएसीएस ने यह पता लगाने के लिए एक जाँच शुरू की है कि क्या रेफरल श्रृंखला चिकित्सकीय रूप से उचित थी या मरीज को उसकी एचआईवी स्थिति के कारण अप्रत्यक्ष रूप से देखभाल से वंचित किया गया था, जो एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 का उल्लंघन होगा।

मुंबई मेट्रो ने रेलगाड़ी पटरी से उतरने की घटना को कम करके आंका

मुंबई : शहर के मेट्रो नेटवर्क में दो महीने से भी कम समय में दो रेलगाड़ियाँ पटरी से उतर गई हैं, जबकि नई लाइनें लगभग चालू होने वाली हैं। महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) द्वारा 24 सितंबर की घटना को सार्वजनिक रूप से ''मामूली तकनीकी गड़बड़ी'' बताए जाने के बावजूद, मामले से परिचित अधिकारियों का कहना है कि 24 सितंबर को शहर में पहली बार मेट्रो पटरी से उतरने की घटना मेट्रो लाइन 9 पर ट्रायल रन के दौरान संचार में आई खराबी के कारण हुई थी। महा मुंबई मेट्रो ने दहिसर में 24 सितंबर की रेलगाड़ी पटरी से उतरने की घटना को कम करके आंका, अधिकारियों का कहना हैपटरी से उतरने की यह घटना सुबह लगभग 5 बजे हुई, जब एक खाली मेट्रो रेक रात भर के परीक्षण के बाद चारकोप डिपो लौट रहा था। मीरा-भायंदर में ट्रायल रन के लिए खड़ी रेक को मेट्रो 2ए और 7 कॉरिडोर से होते हुए मेट्रो 7 लाइन पर जाना था।

इस दौरान, ट्रेन को मैनुअल मोड में रखा गया था और पायलट को बिना सिग्नल के आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, जो एक ऐसी परिचालन स्थिति है जिसके लिए सटीक संचार और निगरानी की आवश्यकता होती है। ओवरीपाड़ा स्टेशन की ओर बढ़ते समय, रेक पटरी से उतर गई।घटना से परिचित अधिकारियों के अनुसार, क्रॉसओवर पॉइंट्स पर सॉफ़्टवेयर-संचालित सिग्नलिंग बेहद महत्वपूर्ण है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''यह संचालन और परीक्षण टीमों के बीच संवाद की कमी की ओर इशारा करता है।'' मेट्रो लाइन 2 और 7, साथ ही लाइन 7अ और 9 के लिए सिग्नलिंग और दूरसंचार परीक्षण, एल्सटॉम द्वारा किए जा रहे हैं।इस दुर्घटना के कारण मेट्रो 2अ और मेट्रो 7 पर पाँच घंटे से ज्यादा समय तक सेवाएँ बाधित रहीं, जिससे दहिसर, अंधेरी पश्चिम और गुंडावली के बीच सुबह के व्यस्त समय में यात्रा बाधित रही।

ट्रेनों को समय से पहले ही रोक दिया गया, और ओवरीपाड़ा और आरे के बीच केवल एक ही ट्रैक उपलब्ध था। कई स्टेशनों पर यात्रियों को बिना किसी कारण बताए प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई।सितंबर की इस दुर्घटना ने 5 नवंबर को वडाला में परीक्षण के दौरान मोनोरेल के पटरी से उतरने की घटना के बाद और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तीन कर्मचारी घायल हो गए थे। दोनों ही मामलों में, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सार्वजनिक रूप से इन दुर्घटनाओं को मामूली गड़बड़ियाँ बताया, जबकि आंतरिक आकलन अधिक गंभीर परिचालन खामियों का संकेत देते हैं।

नगर निगम ने दो वर्षों में सत्तारूढ़ दल के विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को सैकड़ों करोड़ रुपये आवंटित किए

मुंबई : देश के सबसे धनी नगर निगम के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही, इस बात के विवरण सामने आ रहे हैं कि कैसे नगर निगम ने दो वर्षों में सत्तारूढ़ दल के विधायकों, विधान पार्षदों और यहाँ तक कि सांसदों को सैकड़ों करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि विपक्षी विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए निर्धारित इन निधियों से वंचित रखा गया। चालू वित्त वर्ष में, अब तक वितरित की गई राशि ₹418.01 करोड़ है।बीएमसी मुख्यालयसूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्राप्त विवरण से पता चलता है कि फरवरी 2025 में, बीएमसी ने शहर के 36 विधायकों में से प्रत्येक के लिए ₹17.5 करोड़ निर्धारित किए थे - सत्तारूढ़ दल के 27 विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को ये निधि प्राप्त हुई।इस वर्ष आवंटित ₹418.01 करोड़ भाजपा, शिवसेना और राकांपा के 22 विधायकों, तीन विधान पार्षदों और दो सांसदों - राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल - को दिए गए। अधिकांश आवंटन या तो ₹17.50 करोड़ या ₹12.15 करोड़ प्रति व्यक्ति के थे।मार्च 2022 से, जिसके बाद से अब तक नगर निगम चुनाव नहीं हुए हैं, धन आवंटन का मुद्दा विवादास्पद रहा है।

चूँकि शहर में नागरिक कार्य करने के लिए कोई पार्षद नहीं थे, इसलिए बीएमसी ने फरवरी 2023 में विधायकों और सांसदों द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन के लिए बजटीय प्रावधान किए। सभी प्रस्ताव मुंबई के दो संरक्षक मंत्रियों के माध्यम से भेजे जाएँगे।

हरियाणा में अपराधियों की शामत, 2 दिनों में कई जगह हुई छापेमारी में 56 गिरफ्तार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' में सिर्फ दो दिनों में 56 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून का कड़ा संदेश दिया है। इस अभियान का मकसद अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ना, उनकी संपत्तियां जब्त करना और नई वारदातों को रोकना है। जनता-पुलिस की साझी सफलता ने साबित कर दिया है कि हरियाणा अब अपराधियों के लिए ÷नो प्लेस टू हाइड÷ बन चुका है। इस अभियान का नेतृत्व डीजीपी ओपी सिंह कर रहे हैं, और इसकी रणनीति थाना, जिला और राज्य स्तर पर बनाई गई है। हर थाना अपने क्षेत्र के पांच सबसे कुख्यात अपराधियों को निशाने पर रखे हुए है, जबकि हर जिले की टीम 10 टॉप मोस्ट अपराधियों की गिरफ्तारी पर ध्यान दे रही है। एसटीएफ ने राज्यभर के 20 सबसे खतरनाक अपराधियों की सूची तैयार की है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

यह अभियान 20 नवंबर तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क को तोड़ना, नई वारदातों को रोकना और सुरक्षा मजबूत करना है। पहले ही दो दिनों में पुलिस ने कुल 56 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 602 अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई हुई है। यह अभियान अपराधियों में डर पैदा कर चुका है और जनता-पुलिस के सहयोग से सफलता की नई मिसाल कायम की है। अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क को तोड़ना, संपत्तियां जब्त करना, जमानत रद्द करवाना और भविष्य में अपराध रोकना इस अभियान की प्राथमिकता है। पहले ही दो दिनों की सफलता ने दिखा दिया कि हरियाणा अब अपराधियों के लिए ÷नो प्लेस टू हाइड÷ बन चुका है और कानून पूरी तरह अपना नियंत्रण बनाए हुए है। पहले दो दिनों की जबरदस्त सफलता ने दिखा दिया कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन कितना असरदार है। 5 नवंबर को एक ही दिन में 32 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, वहीं 6 नवंबर को 24 और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 252 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। इन दो दिनों में 9 हिस्ट्रीशीट भी खोली गईं, जिससे अपराधियों का रिकॉर्ड अपडेट हुआ और भविष्य में उनकी जमानत रद्द करने की प्रक्रिया तेज़ हुई।

सुवेंदु का ममता पर तीखा हमला कहा- बंगाल में दुष्कर्म जैसी घटना को दबाती है पुलिस

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली पर नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असफल करार दिया है। तारकेश्वर में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय अपराध दबाने में लगी है। परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, फिर चंदननगर रेफर कर दिया। सुवेंदु ने सवाल उठाया कि तारकेश्वर पुलिस कानून की रक्षा कर रही है या ममता के चाटुकार बनी हुई है? उन्होंने कहा कि यह ममता बनर्जी के बेलगाम शासन का असली चेहरा है। हर बार एक ही कहानी– बलात्कार, एफआईआर न होना या देरी, अस्पताल रेफर, मीडिया ब्लैकआउट और टीएमसी नेताओं का पर्दाफाश। ममता बनर्जी, आपके राजनीतिक अस्तित्व के लिए और कितनी मासूम बेटियों की जान कुर्बान करनी पड़ेगी?

सुवेंदु ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके शासन में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस सच्चाई दबाकर राज्य की नकली छवि बचा रही है। तारकेश्वर पुलिस ने अपनी शपथ भुला दी है। यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है, जो राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की पोल खोलती है। इससे पहले सुवेंदु ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केएमसी अवैध तरीके से जन्म प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। इनका मकसद वास्तविक नागरिकों की मदद नहीं, बल्कि उन संदिग्ध व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना है, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। एक्स पर पोस्ट में सुवेंदु ने चुनाव आयोग से तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने लिखा कि यह मतदाता सूची में हेरफेर और लोकतंत्र को कमजोर करने का घोर प्रयास है। जन्म प्रमाणपत्र कानूनी दस्तावेज हैं, जो नवजात शिशुओं या दुर्लभ मामलों में देरी से पंजीकरण के लिए जारी होते हैं। ये राजनीतिक हथियार नहीं, जिनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए जनसांख्यिकी बदलने में हो। भाजपा नेता का कहना है कि टीएमसी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। बच्ची बलात्कार जैसी जघन्य घटना में पुलिस की निष्क्रियता और फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों का खेल राज्य में कानून की मौत का प्रमाण है। सुवेंदु ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि असफल शासन की यही पहचान है अपराध दबाओ, सच्चाई छिपाओ, वोट बैंक बनाओ। चुनाव आयोग और जनता से अपील की कि ऐसे खेल को रोका जाए। बंगाल की जनता अब जाग रही है और ममता के इस बेलगाम शासन को जवाब देगी।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में सांस लेना हुआ दूभर, 350 के पार हो गया एक्यूआई

फरीदाबाद (एजेंसी)। ठंड की शुरुआत होते ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में सांस लेना दूभर हो गया है। यहां एक्यूआई 350 के पार हो गया है। मौसम और औद्योगिक गतिविधियों के चलते इन दोनों शहरों की हवा सांस लेने के लिए हानिकारक बनी हुई है। गुरुग्राम में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) औसतन खराब श्रेणी में है, लेकिन अलग-अलग इलाकों में यह स्तर काफी अलग दिख रहा है। उदाहरण के लिए सेक्टर 47 में एक्यूआई 358 दर्ज किया गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं, शहर के अन्य हिस्सों का औसत एक्यूआई 143 के आसपास है जो सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। इसका मतलब यह है कि सेक्टर 47 और आसपास के लोग आज अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें और लंबी अवधि तक बाहर रहने से बचें। बल्लभगढ़ में आज का एक्यूआई 157 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। यहां पीएम 2.5 प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है। पीएम 2.5 छोटे कण होते हैं जो सांस के रास्ते आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहने से सांस की बीमारी, एलर्जी और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग विशेष सतर्कता बरतें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।सामान्य लोगों के लिए भी आज मास्क पहनकर बाहर निकलना और व्यायाम या लंबी पैदल यात्रा को सीमित करना बेहतर होगा। घर के अंदर हवा को शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल और खिड़कियां बंद रखना फायदेमंद हो सकता है। कुल मिलाकर आज गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सामान्य से खराब है और सभी लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है।

यहां एक्यूआई बेहद खराब

वहीं फरीदाबाद की बात करें तो यहां आज का कुल एक्यूआई स्तर अस्वस्थ श्रेणी में है जिसका औसत लगभग 204 है। फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता में अंतर देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सेक्टर 11 का एक्यूआई 275 है, जो खराब श्रेणी में आता है। न्यू इंडस्ट्रियल टाउन और नरेला राजीव नगर में एक्यूआई क्रमशः 230 और 230 दर्ज किया गया है, जो भी खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि फरीदाबाद में औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों के धुएं के कारण वायु में प्रदूषकों का स्तर काफी अधिक बढ़ गया है।

विपक्ष की लोगों को डराकर वोट हासिल करने की रणनीति और सोच गलत

-चिराग बोले- जब कोई नया बहाना नहीं मिला तो एसआईआर को मुद्दा बना लिया

पटना(एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव को उनके हालिया बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को डराकर वोट हासिल करने की रणनीति और सोच गलत है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में विपक्षी दलों के नेता मुद्दों से भटक जाते हैं और बेवजह के मुद्दों पर लोगों को गुमराह कर वोट हासिल करना चाहते हैं। विपक्षी दलों की यह सोच अच्छी नहीं है।

चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले एसआईआर जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, दावा किया जा रहा था कि एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आपको कोई ऐसा मतदाता मिला जिसने कहा कि उसका वोट काट लिया गया है? यह लोग ईवीएम को दोषी ठहराते है, जब कोई नया बहाना नहीं मिला तो एसआईआर को नया मुद्दा बना लिया।

चिराग ने आगे कहा कि एसआईआर का न तो सरकार से और न ही हमारे राज्य के लोगों से कोई लेना-देना है। हर चुनाव में विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश की है। यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है, जब भी चुनाव आते हैं, वे एक झूठी कहानी बनाते हैं, गलत सूचना फैलाते हैं और डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि एनडीए की सरकार फिर से आई तो देश में आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को सवा साल से ज्यादा हो गया है। मैं विपक्षी दलों के नेता से पूछता हूं कि क्या संविधान और लोकतंत्र खत्म हो गया।

एसआईआर का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर विपक्षी दलों को लगता है कि एसआईआर उनके लिए मुद्दा है तो एक बार भी अधिकृत आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच गलत है।

बेंगलुरू की जेल में मौज काट रहे आतंकी, मोबाइल पर घंटो बात करते और टीवी देखते हैं कैदी

बेंगलुरू(एजेंसी)। बेंगलुरु की जेल में आतंकियों को घर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उनके एशो आराम में कोई कमी नहीं है। खतरनाक आतंकी यहां कभी घंटों मोबाइल पर बात करते हैं तो कभी टीवी देखकर अपना मनोरंजन करते नजर आते हैं। इसी तरह का वीडियो वायरल होते ही कर्नाटक में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए छह वीडियो में आईएसआईएस के हैंडलर जुहाद हामिद शकील मन्ना, सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर उमेश रेड्डी जैसे खूंखार कैदी मोबाइल फोन पर बातें करते, टीवी देखते और अन्य सुविधाओं का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों की शिकायत रहती है कि जेल के आसपास लगे नेटवर्क जैमर उनकी मोबाइल सिग्नल बाधित कर रहे हैं, लेकिन कैदी बिना रुकावट फोन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं रिपोर्ट मंगवाऊंगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। एडीजीपी (जेल) बी दयानंद ने जांच के आदेश जारी किए हैं। इसमें फोन मुहैया कराने वालों, शामिल अधिकारियों की भूमिका और वीडियो लीक करने वालों की पहचान होगी। एडीजीपी (जेल) पीवी आनंद रेड्डी ने जेल का दौरा किया और कैदियों व स्टाफ से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में वीडियो 2023 और 2025 के पाए गए। वायरल वीडियो में से तीन वीडियो 2023 के बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी हाल के हैं। इस सुरक्षा चूक ने न केवल जेल प्रशासन को शर्मसार किया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वीडियो में आईएसआईएस के कुख्यात हैंडलर जुहाद हामिद शकील मन्ना को स्मार्टफोन और बेसिक हैंडसेट पर बात करते हुए देखा गया है।

महाराष्ट्र में बड़ा सवाल: क्या निकाय चुनावों में टूट जाएगा उद्धव और शरद पवार के साथ कांग्रेस का गठबंधन?

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस अगले सप्ताह यह फैसला करेगी कि राज्य में चुनावों के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं।

खबरों के मुताबिक यह निर्णय 12 नवंबर को होने वाली महाराष्ट्र कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सबसे पहले सभी जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी, जिसके बाद राज्य के वरिष्ठ नेता विचार-विमर्श करेंगे और अंतिम फैसला लेंगे। बैठक में यह तय होने की उम्मीद है कि कांग्रेस को अपने महा विकास आघाडी (एमवीए) सहयोगियों शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर पार्टी के भीतर विरोध है। पिछले कुछ महीनों से, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई एवं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हाथ मिलाने के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उनके जिला संसदीय बोर्ड दो दिसंबर को होने वाले 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार पूरे करने और संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाने की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों ने बताया, 'ब्लॉक स्तर के नेता स्थानीय स्तर पर चुनाव रणनीति की देखरेख कर रहे हैं और जिला इकाई प्रमुख अपने-अपने क्षेत्रों का प्रबंधन कर रहे हैं, जबकि प्रमुख नेता संभाग स्तर पर गतिविधियों की देखरेख, रणनीति और प्रचार कर रहे हैं।' राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक 29 नगर निगमों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, जिनमें मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका, 32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियां शामिल हैं, जहां चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरे होने हैं। उन्होंने कहा, हमने अपने स्थानीय नेताओं से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति के अनुसार केवल कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन दलों के साथ गठबंधन पर फैसला लें। सूत्रों ने कहा, 'हमें 6,859 सीट के लिए उम्मीदवारों से 35,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।' दो दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया कि पार्टी के लिए चुनाव में अच्छी संभावना है क्योंकि ग्रामीण मतदाता बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज को लेकर सरकार से 'नाराज' हैं। सूत्रों ने कहा कि उनके अनुसार 'वोट चोरी' का उनका मुद्दा जमीनी स्तर पर पहुंच गया है। पार्टी नेताओं के अनुसार, प्रदेश इकाई ने स्थानीय चुनाव की तैयारी के लिए सूक्ष्म स्तर की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के बूथ प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं।

धर्मेंद्र से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचें एशा देओल के एक्स हसबैंड, बीते साल पत्नी से लिया था तलाक...

धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं। 89 साल के अभिनेता का वहां इलाज चल रहा है। जहां उनसे मिलने के लिए और उनका हालचाल लेने के लिए सलमान खान से लेकर शाह रुख, आमिर खान, गोविंदा सहित कई सितारे पहुंचे हैं। इस वक्त धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी से लेकर उनके सभी बच्चे अस्पताल में उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस बीच ही एशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी को भी ब्रीच कैंडी अस्पताल से बाहर निकलते हुए मीडिया ने अपने कैमरे में कैप्चर किया।

भरत तख्तानी अपने एक्स ससुर धर्मेंद्र से अस्पताल में मिलने उस समय पहुंचे, जब वह अभय देओल, सनी देओल सहित पूरा परिवार मौजूद था। अस्पताल से निकलते हुए भरत के चेहरे पर धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखाई दी। भरत और एशा भले ही एक-दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन बिजनेसमैन का धर्मेंद्र के साथ काफी अच्छा रिश्ता रहा है।

इससे पहले लगातार पिता धर्मेंद्र की डेथ की उड़ रही अफवाहों पर पूर्णविराम लगाते हुए एशा देओल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने गुस्सा पिता के निधन को लेकर उड़ी झूठी अफवाहों पर गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, ''लगता है मीडिया ज्यादा ही एक्टिव हो गई है और गलत न्यूज फैला रही है। मेरे पिता ठीक हैं और रिकवरी कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारी फैमिली को प्राइवेसी दें। मेरे पिता की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद''।

'ओजैंपिक लेकर घटाया वजन...' आरोपों पर तमन्ना भाटिया ने तोड़ी चुप्पी, वेट लॉस की बताई वजह

तमन्ना भाटिया अब सिर्फ साउथ का ही नहीं, बॉलीवुड का भी जाना-माना नाम बन चुकी हैं। एक्ट्रेस ने पिछले दिनों अपने डांस नंबर्स से खूब सुर्खियां बटोरीं। उनके 'आज की रात हो' या फिर 'गफूर', तमन्ना के साभी डांस नंबर हिट रहे। इस बीच अपनी कर्वी बॉडी को लेकर भी तमन्ना ने खूब सुर्खियां बटोरीं और अब एक्ट्रेस अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं। पिछले कुछ महीनों में ही तमन्ना ने कई किलो वजन कम कर लिया है और उनका ये वेट लॉस देखने के बाद जहां उनके कुछ फैंस खुश हैं तो कुछ सोशल मीडिया यूजर एक्ट्रेस पर ओजैंपिक के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में तमन्ना ने अब खुद सामने आकर अपने वेट लॉस और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के प्रेशर पर भी बात की।

हार्पर बाजार के साथ बातचीत में तमन्ना भाटिया ने अपने वेट लॉस और बॉडी पर बात की। उन्होंने ओजैंपिक लेने के आरोपों पर रिएक्ट करते हुए कहा- 'मैं कैमरे के सामने ही बड़ी हुई हूं। मैं 15 साल की उम्र से कैमरे के सामने रही हूं तो छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मेरे कर्व्स कहीं नहीं जा रहे हैं। मेरे 20२ के आखिरी तक, मेरा शरीर दुबला-पतला ही था। मेरा शरीर हमेशा से ऐसा ही रहा है। टेक्निकली ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं ऐसे ही पली-बढ़ी हूं और ऐसी ही रही हूं।' तमन्ना भाटिया आगे कहती हैं- 'ये हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं लगभग 100 फिल्में कर चुकी हूं और लोगों ने मुझे अलग-अलग फिल्मों में अलग-अलग शरीर में देखा है। लेकिन, ज्यादातर फिल्मों में मैं दुबली-पतली ही रही हूं। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि महिलाओं का शरीर बदलता रहता है, हर पांच साल में हम खुद का एक अलग रूप देखते हैं।'

तमन्ना भाटिया ने बताया कि कैसे कोरोना ने उनके शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और इस दौरान उनके लिए अपना वजन मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। तमन्ना ने कहा- 'मेरे केस में, कोरोना ने मेरे शरीर को काफी प्रभावित किया। मैं अपने 20२ के आखिरी में थी और मेरे लिए ये मुश्किल हो गया था कि अपने वजन को मेंटेन कर पाऊं। मैंने इससे बहुत संघर्ष किया। मुझे अपना दाल, चावल और रोटी खाना बहुत पसंद है। ये सारी हेल्दी चीजें रते हुए भी, मुझे कैमरे के सामने जाना ही पड़ता था और मुझे लनगे लगा कि मैं किसी खास साइज में नहीं रहना चाहती और मैं लगातार इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूं। मुझे लगने लगा, ओह, क्या मेरा पेट बाहर आ रहा है? क्योंकि एक समय ऐसा भी आया, जब मेरा पेट बाहर आने लगा था और मैं सोच में पड़ गई कि मेरे शरीर को क्या हो रहा है।'

हीरोइन बनने के लिए घर से भागी, 1 शो से बनी स्टार, फिर टूटा दुखों का पहाड़... आंखों के सामने बॉयफ्रेंड ने तोड़ा था दम

फिल्मी दुनिया में ऐसे कई स्टार हैं, जिन्होंने अपना सपना पूरा करने की खातिर परिवार से बगावत कर दी। कई ने तो अभिनय की दुनिया में पहचान बनाने के लिए अपना घर ही छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ इस एक्ट्रेस ने भी किया। हीरोइन बनने की ख्वाहिश अपनी आंखों में लिए इस एक्ट्रेस ने अपने परिवार से बगावत कर दी और घर छोड़ दिया, जिसके बाद परिवार ने भी इससे नाता तोड़ लिया। लेकिन, फिर एक शो ने इसे रातों-रात स्टार बना दिया और फेम के साथ घरवालों का प्यार भी इस एक्ट्रेस की झोली में आ गिरा। हम यहां जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं शहनाज गिल हैं, जिन्हें सलमान खान के शो बिग बॉस ने घर-घर में मशहूर कर दिया था। शहनाज गिल बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा थीं। जब उन्होंने शो में एंट्री ली तो अपने क्यूट अंदाज से सबको अपना दीवाना बना दिया। धीरे-धीरे शहनाज की लोकप्रियता बढ़ती गई और वह इस सीजन की सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक बन गईं। अपने भोलेपन से दर्शकों के दिल जीतने वालीं शहनाज ने टॉप 5 तक अपनी जगह बनाए रखी। पूरे शो के दौरान शहनाज चर्चा में बनी रहीं, इसी दौरान वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात करती नजर आईं। उन्होंने शो के दौरान ही अपनी जर्नी पर भी बात की थी और खुलासा किया था कि वह हीरोइन बनने के लिए घर से भाग गई थीं।

शहनाज गिल बिग बॉस 13 के दौरान कई मौकों पर इस बारे में बात करती दिखीं कि उनका परिवार नहीं चाहता था कि वह एक्ट्रेस बनें, इसलिए वह अपना घर छोड़कर भाग गई थीं। शहनाज ने बताया था कि कैसे उनके घर से भागने के बाद उनके घरवालों ने उनसे नाता तोड़ लिया था। उन्होंने भी कसम खा ली थी कि जब तक फेमस नहीं हो जातीं, वह घर नहीं जाएंगी, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार वालों को ब्लॉक कर दिया था।

वह कभी-कभी सिर्फ अपनी मां से बात किया करती थीं। हालांकि, शो के दौरान उनके पिता उन्हें सपोर्ट करने बिग बॉस हाउस में पहुंचे थे, जिन्हें देखकर शहनाज बेहद खुश थीं।

बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार आरोपी वसई कोर्ट से फरार; पुलिस ने पानी के ड्रम में छिपा हुआ पाया

नालासोपारा : 12 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया 23 वर्षीय युवक वसई कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया। 30 मिनट की तलाशी के बाद, पुलिस ने उसे कोर्ट के पास एक गाँव में पानी के ड्रम में छिपा हुआ पाया। आरोपी दानिश खान कोर्ट के पास एक गाँव में एक सुनसान घर में मिला। उत्तर प्रदेश के रहने वाले और संतोष भुवन इलाके में रहने वाले नाबालिग पीड़िता के माता-पिता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी दानिश खान को गिरफ्तार किया गया। लड़की के बयान के अनुसार, आरोपी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। तुलिंज पुलिस ने शुरूआत में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 (बलात्कार), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 (गंभीर यौन उत्पीड़न), 8 (यौन उत्पीड़न) और 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया था।

क्रूर बलात्कार के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी। मामला संवेदनशील और गंभीर होने के कारण, नालासोपारा पुलिस की अपराध शाखा-2 की टीम ने मामले की जाँच शुरू की। 48 घंटों के भीतर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविराज कुराडे के मार्गदर्शन में टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और आरोपी की पहचान खान उर्फ जमीर के रूप में की। सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल ने कहा, ''वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ वाहन चोरी के पहले भी मामले दर्ज हैं।''अपराध शाखा ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जाँच के लिए उसे पेल्हार पुलिस को सौंप दिया। सोमवार दोपहर 3 बजे, अदालत में पेश होने से पहले ही, खान शौचालय जाने के बहाने भाग गया। जब वह कुछ देर बाद भी नहीं लौटा, तो अधिकारियों ने अदालत परिसर में उसकी तलाश की और फिर आस-पास के गाँवों और घरों में भी तलाशी ली। कुछ ही मिनटों में, गाँव के निवासियों ने भी आरोपी को ढूँढ़ने में उनकी मदद की। राहगीरों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उसे वसई पंचायत समिति की एक वाड़ी में जाते देखा था। फिर अधिकारियों ने उसे एक सुनसान घर में पानी के ड्रम में छिपे हुए पाया। फिर वे उसे वापस अदालत ले गए और वसई के एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।

तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की चली गई जान

नवी मुंबई : तलोजा, कलंबोली और सीवुड्स में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की जान चली गई। इनमें से दो तेज गति और एक लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ। पहला हादसा रविवार को कलंबोली में हुआ। एक 42 वर्षीय वकील अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थीं। दोपहर करीब 2.51 बजे, जब वे पुरुषार्थ ब्रिज के पास थे, सायन-पनवेल हाईवे पर एक कथित तौर पर तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस शिकायत के अनुसार, उनके पति को मामूली चोटें आईं। आरोपी चालक की पहचान बिहार के जमुई निवासी 37 वर्षीय छोटन कार खुबलाल यादव के रूप में हुई है। कलंबोली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और 281, तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे बीएनएस धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है।दूसरी दुर्घटना रविवार सुबह लगभग 8.45 बजे तलोजा में हुई, जहाँ 55 वर्षीय पैदल यात्री मिलिंद भीकाची सुरदकर को नवाडे ब्रिज के पास सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी, 42 वर्षीय नवाब अली बरकत अला मनिहार के अनुसार, सुरदकर को टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक तुरंत भाग गया। पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तलोजा पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125(ए) और (बी) (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134(ए) और (बी) (दुर्घटना की स्थिति में चालक का कर्तव्य) तथा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया है।रविवार रात लगभग 10.41 बजे, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 28 वर्षीय प्रदीप अशोक सोलंकी की सीवुड्स रेलवे पुल के पास हुई टक्कर में मौत हो गई। 38 वर्षीय यज्ञेश्वर रमेश कोली द्वारा कथित तौर पर लापरवाही से चलाए जा रहे हीरो विडा वी1 प्रो स्कूटर ने सोलंकी की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह बाइक से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। आरोपी कोली को बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है। एनआरआई कोस्टल पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(बी) और 106(1) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है।

नवी मुंबई में सुरक्षा कड़ी : यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान

नवी मुंबई : दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद नवी मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां शहर के रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हवाई अड्डा और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच कर रही हैं। स्थानीय पुलिस ने कहा कि यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी यात्री बैगेज और पार्सल की जांच की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें।

बम और डॉग स्क्वॉड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे स्टेशनों पर सघन निरीक्षण किया और संदिग्ध सामान की पहचान की। साथ ही, बस टर्मिनलों और प्रमुख सड़कों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। स्थानीय अधिकारी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक संसाधनों को सक्रिय किया गया है। पुलिस ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

इस दौरान एनएसजी और अन्य विशेषज्ञ टीमों को भी संभावित खतरों की जांच के लिए तैनात किया गया है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों से बचें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के मद्देनजर शहर की सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण रखा गया है। नवी मुंबई में सुरक्षा बढ़ाने के इस कदम से नागरिकों और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानक लागू किए जाएं। इस कार्रवाई के तहत प्रमुख रेलवे और बस टर्मिनलों में सीसीटीवी निगरानी और यात्री जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आवश्यक होने पर और कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। यह कदम दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। प्रशासन और पुलिस मिलकर नागरिकों की सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भयंदर पश्चिम में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

मुंबई : मीरा भयंदर में घोटाला नहीं, बल्कि मेहता स्टाम्प घोटाला हुआ है, लेकिन सबूतों के साथ शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, महा विकास अघाड़ी और मनसे के विरोध प्रदर्शन के दौरान इन दोनों घोटालों में मामला दर्ज करने की मांग की गई। भयंदर पश्चिम में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के सामने कांग्रेस, ठाकरे सेना, मनसे ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्थ पवार पुणे में कथित जमीन खरीद घोटाले और स्टाम्प धोखाधड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

इस संबंध में संयुक्त उप पंजीयक को एक अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें 1,800 करोड़ रुपये की जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपये दिखाई गई, लेकिन स्टाम्प शुल्क केवल 500 रुपये था। सभी आम नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए और प्रत्येक स्टाम्प शुल्क के लिए केवल 500 रुपये ही लिए जाने चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत, पूर्व नगरसेवक अनिल सावंत, राजीव मेहरा, प्रकाश नागणे, मनसे शहर अध्यक्ष संदीप राणे, सचिन पोपले, अनिल रानावड़े, ठाकरे सेना शहर संगठक नीलम धवन, जिला प्रमुख प्रभाकर म्हात्रे, उप जिला प्रमुख मनोज मयेकर, धनेश पाटिल, प्रकाश सावंत आदि तीनों दलों के पदाधिकारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर 4 ए, फ्लोर-जीआरडी, 29 डी, शबन हाउस, वंजावाडी लेन, माहिम वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhani.com